Deposit by public sector institutions *to* Associate Bank of SBI

1050. SHRI JOYANTA ROY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps to prevent the depositing by the public sector instiutions to the Associate Banks of State Bank of India; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASEKHARA MURTHY): (a) and (b) In the light of the recommendations of the Joint Parliamentary Committee (IPC) which enquired into the irregularities in securities and banking transactions, Government have laid down guidelines governing investment of surplus funds by Public Sector Enterprises (PSEEs) to avoid recurrence of misuse of funds. The said guidelines, jnter-alia, provide that investments may be made by the PSEs in term deposits with any scheduled commercial bank with a paid up capital of at least Rs. 100 crores, fulfilling the capital adequacy norms as prescribed by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. The question of amending the guidelines to take into accounts the net worth of a bank instead of paid up capital is under consideration of the Government.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को ऋण

1051. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को राज्य-वार कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है :

(ख) इससे राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए है ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान बैंक-वार ऋण गुणों की क्या स्थिति थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अर्थव्यवस्था की गतिहीनता

1052. श्री ईश दत्त यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था तेजी से गतिहीनता की ओर बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या विशेष उपाय कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता :

बकाया उत्पाद शुल्क

1053. श्री ईश दत्त यादव :
श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरौला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करीब 160 कम्पनियों पर उत्पाद शुल्क बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो गत नवम्बर, तक उत्पाद शुल्क की कुल कितनी राशि बकाया थी ; और

(ग) सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क की उक्त राशि प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं और इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राजस्व बकाया के बारे में सूचना कम्पनी-वार नहीं रखी जाती है। तथापि, 30 नवम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार